श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप स्टेटमेंट को देखें जो बहुत लम्बा चौड़ा है। आप जवाब को और स्टेटमेंट दिखाई को देखें।

"6 The rates of post matrica scholarships should be increased two-fold and the means tests for award of these scholarships to scheduled castes students should be dispensed with.

The rates of post-matric scholarships have been increased with effect from the academic year 1974-75. The means test for the scheduled castes has also been liberalised by raising the limit from Rs.500/- to Rs. 750 per month.'

ऊपर की लिमिट तो बढ़ा दी है लेकिन जो दिन भर काम करेगा, मजदूरी करेगा वह स्कालरशिप नहीं पा सकता है।

श्री ओम मेहता: शैडयूल कास्ट्स और शैडयूल ट्राइब्ज के लोगों से हमें मुतवातर यह डिमांड मिल रही थी कि जो रेट्स है इनको बढ़ाया जाए। इस वास्ते गर्वनमेंट मे इन रेट्स को ड्योढा और डबल भी किया है। आप देखें कि पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप हम साढे तीन लाख लड़कों को दे रहे हैं। जो रेट्स है वे 125 रुपए से लेकर 40 रुपए तक हैं। जो स्कालर हैं जो छोटी क्लास मे हैं उनको चालीस रुपए देते हैं और जो दूसरी क्लासिस मे होस्टल में हैं उनको 125 रुपए देते है। हम चाहते हैं कि बैनीफिट ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले इस वास्ते हमने 200 करोड़ रुपया पांचवीं योजना में सिर्फ इसलिए रखा है कि पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप जो है वे शैडयूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को दिए जा सकें और लोग जो खुद कमाते हैं और उसके बाद स्कालरशिप भी लेते है उनको इससे बिचार किया गया है और यह इसलिए किया गया है कि ताकि ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके, उनको पहुंच सके, जिन को कोई फायदा अभी नहीं

Development of Hilly Areas

*22 PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Central Government have given any priority for the various projects in the sphere of Railways, roads, industrialisation, hydel generation, irrigation and drinking water for the development of hilly areas of the country;

(b) if so, whether any allotment has been made for the purpose in the Fifth Five Year Plan; and

(c) if so, the allotment made in each one of these Sectors/Departments so as to ensure proper development of hilly regions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) While the responsibility for the development of hill areas rests primarily with the State Governments concerned, the Central Government also evince special interest in accelerating the progress of hill areas as is evident from the proposal in the draft Fifth Five Year Plan to provide additional Central assistance to the States on liberalised terms for development of hill areas. Further, schemes relating to industrialisation, irrigation and hydel-generation in hill areas (as also in other backward areas) receive

(b) and (c). A sum of Rs. 500 crores has been proposed as additional Central assistance in the draft Fifth Five Year Plan for hill and tribal areas. The break-up of this amount for areas/sectors has not yet been finalised.

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है । उन्होंने यह भी कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की बहुत जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकारों की है । मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार का भी इस में भारी दायित्व है क्योंकि आज भी कई विभाग केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उन विभागों में भी क्या वह उसी प्रकार से इन विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में विशेष दिलचस्पी लेंगे जिस प्रकार कें प्रान्तीय कार्यों के बारे में लेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह तो मैं ने अपने मूल उत्तर में ही कहा है कि यद्यपि यह विषय राज्य सरकारों के अन्तर्गत आता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों की जो खास समस्यायें हैं, और उन का जो विशेष महत्व है, उस के कारण हम अपने केन्द्रीय क्षेत्र से भी उन की सहायता कर रहे हैं और उस के लिए हम ने अपनी पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के प्रारूप में काफी बड़ी राशि का प्रावधान किया है ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन ले सकता हूं कि इस 500 करोड़ रुपए की राशि में कोई कटौती नहीं होगी और जो विकास-कार्य विभिन्न मंत्रालयों ने शुरू किए हैं, वे जारी रहेंगे और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का रवैया सहानुभूतिपूर्ण रहेगा ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह बात तो बिना कहे भी मानी जा सकती है कि हमारा रवैया पूर्णरूप से सहानुभूतिपूर्ण रहेगा । जहां तक कटौती का सवाल है, उस के बारे में किसी प्रकार का आश्वासन हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारी पांचवीं पंच-वर्षीय योजना का जो प्रारूप बना है, हम अपनी वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देख कर उस को फिर से ऐसा बना रहे हैं, जिस से हम उसे ठीक ढ़ंग से और जल्दी लागू कर सकें । इस प्रक्रिया में यदि थोड़ा बहुत, यहां वहां, एडजस्टमेंट करना पड़ा, तो करेंगे, मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जहां तक हो सकेगा, हम लोग पहाड़ी इलाकों की उन्नति और विकास-योजनाओं में कमी नहीं होने देंगे, और हमारी जो मूल नीति है, उस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

SHRI NOORUL HUDA: Government know that the North Kachar hills and Mikir Hills are the only hilly areas still part of Assam and these are among the most backward regions in the country. Will special attention be given for the development and industrialisation of these areas still forming part of Assam because Meghalaya, Mizoram, Nagaland and NEFA have been separated from Assam?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: We are giving special attention to these two districts of Assam. The hon. member need not have any apprehension that not enough attention is being given to them just because they are still with Assam. They are being treated as hill districts and special attention will be given to them.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: In the Fourth Plan period, has it come to the notice of Government that funds allocated for the development of backward and hilly areas to State Governments were to a great extent utilised for development of advanced areas in those States? If so, what special guarantees and safeguards are the Central Government devising in the Fifth Plan to see that funds allotted for the backward regions are really spent in those areas and not diverted elsewhere? Also have Government been seized of this matter that many MPs are campaigning for the development of backward regions which

the Prime Minister also inaugurated? Was a specific suggestion given for the setting up of a Backward Areas Development Authority with money diverted to this Authority which will spend it?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA It cannot be denied that instances of diversion may have taken place earlier To avoid it during the Fifth Plan, we have devised a system of sub-plans according to which we determine specific areas and specific plans for these hilly areas and other specified tribal areas So the hon member can be assured that the difficulties faced in the past in certain cases will be avoided this time

SHRI PARIPOORNANAND PAINULI In view of the fact that the hill regions all over the sub-Himalayan belt are sparsely populated where communication facilities are rarely available and the development programme is hardly commensurate with the needs of the hill people, will the recommendations of the ARC Task Force, the National Commission on Agriculture and other expert bodies be taken into account while finalising the Fifth Plan targets with specific reference to the UP hilly areas?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA All those recommendations are taken into consideration while the Fifth Plan was drafted and the result is that much greater emphasis to hill areas has been given in the Fifth Plan than was given in the earlier plans and this should convince the hon. Member that we are very much alive to the problems of the hill areas.

श्री हुकम चन्द कछवाय क्या यह सही है कि पर्वतीय क्षेत्रों मे वर्षा के दिनो मे काफी पहाड़ और मिट्टी गिरती है, जिस से नदियां भर जाती है और भयंकर बाढ़ आ जाती है, यदि हां, तो क्या पहाड़ों मे बड़ी संख्या मे पेड़ लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है, जिस से पेड़ मिट्टी को पकड़ कर रखे, मिट्टी न गिरे और बाढ़ न आ सके।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : बहुत अच्छा विचार है।

श्री विद्याचरण शुक्ल . माननीय सदस्य, ने बहुत उत्तम बात कही है और इसकी तरफ हमारा पूरा ध्यान है। यह काम हम एक मिले-जुले कार्यक्रम के अन्तर्गत करते हैं, जिस के अनुसार हम ने जमीन को बहने से रोकना है, लैंड-स्लाइड्ज की रोक थाम करनी है, पहाड़ो और जगलो को बचाना है और डैम्ज के सिल्टिंग को रोकना है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस म बहुत सी बातो का फायदा होगा और हम ने उस को बहुत ऊंची प्राथमिकता दी है।

श्री सी० सी० गोहेन · अध्यक्ष महोदय, सवाल पूछने से पहले मे कुछ बातो को रेफर करना चाहता हूं, ताकि आप को सब कुछ मालूम हो जाए। शायद आप को मालूम होगा कि पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी इलाको में रेलवे लाइन बिल्कुल नही है। इस का परिणाम यह है कि मेम्बरो को रेल से जाने के लिए जो फ्री पास दिए जाते हैं, वे हमारे किसी काम नहीं आते हैं। आप को मालूम होगा कि अरुणाचल प्रदेश मे पहले रोड्ज भी नही थे। 1962 में चाइनीज ने हमारे देश पर आक्रमण किया। उस के बाद हमारे इलाके मे कुछ रास्ते बनाए गए। टास्क फोर्स ने जो रास्ते बनाए, उन के बारे में कहा गया कि वे आर्मी के लिए है, पब्लिक के लिए नहीं। इस लिए पब्लिक को उन रास्तो से कोई फायदा नही हुआ। वे रास्ते भी इन-कम्पलीट पड़े हुई है। मैं आप की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मैं इस महीने की 12 तारीख को घर गया। रास्ते में डाइवर्जन खराब था। वहां हमारी जीप अटक गई और हम को सारी रात जंगल के बीच जीप में ही

बितानी पड़ी, जहां कोई खाना और पानी नहीं मिल सकता था।

जहां तक एजूकेशन, शिक्षा, का सम्बन्ध है, हमारे वहां स्वतंत्रता के बाद एजूकेशन शुरू की गई। लेकिन वहां स्थिति यह है कि एक साल शिक्षा का मीडियम आसामी होता है, दूसरे साल हिन्दी होता है और तीसरे साल इंगलिश होता है।

ऐसे ही हमारे लड़कों की हर साल में बदली होती है। हमारे वे लड़के कैसे पढ़ेंगे? कौन से माध्यम से पढ़ेंगे? इसलिए इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कुछ साल पहले वहां इंग्लिश थी, अभी हिन्दी में चेंज करना चाहते हैं। इसलिए मैं हिन्दी में बोल रहा हूं। मैं हिन्दी स्कूल से नहीं पढ़ा हूं लेकिन मैं हिन्दी बोल रहा हूं। अच्छा तो नहीं बोल सकता हूं।

इंडस्ट्री नाम लेने को कोई वहां नहीं है लेकिन सामान बहुत है। ऐसे ही हमारे देश में पावर शार्टेज इतनी है, वहां वाटर रिसोर्सेज बहुत हैं जिन से हाइडिल बिजली पैदा कर सकते हैं। उस के लिए कमेटी में बोलते हैं कि लाइन देना बहुत मुश्किल है, उस में खर्चा ज्यादा पड़ेगा। इसी तरह देखिए, वहां पर तेल निकलता है। उस तेल को बरौनी तक ले जाने के लिए पाइप लाइन लगाना पड़ेगी। उस के लिए क्या खर्चा नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। प्रेसीडेंट्स ऐड्रेस आएगा, बजट आएगा उस पर ये सारी बातें कह लीजिएगा।

श्री सी०सी०गोहेन: मेरा प्रश्न यह है कि अरुणाचल के डेवलपमेंट के लिए मंत्री महोदय ने क्या स्टेप्स लिए हैं? पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उस के डेवलपमेंट के लिए क्या स्पेशल स्टेप्स लिए हैं वह बताएं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के जितने जिले हैं उन सब को विशेष रूप से विकसित करने के लिए हमने अपनी विशेष योजना में सम्मिलित किया है। जहां तक हमारे लिए संभव होगा उस में रेल, शिक्षा, सड़क, उद्योग, बिजली इत्यादि इन सब के बारे में इसी विशेष योजना के अन्तर्गत प्रावधान हम करेंगे।

जहां तक कि सड़क का सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है यह प्रश्न कई दूसरे प्रश्नों से जुड़ा हुआ है पर चूं कि माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को सदन में उठाया है इस के बारे में हम लोग जांच पड़ताल करेंगे जिस से कि सामान्य नागरिकों को इन सड़कों का उपयोग करने में उस तरह की कठिनाई न हो जिस तरफ कि माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है।

शिक्षा और शिक्षा का जो माध्यम है उस के बारे में भी गृह मंत्रालय के द्वारा एक निश्चित नीति का अनुसरण किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस निश्चित नीति से जो पिछली कठिनाइयां रही हैं अरुणाचल प्रदेश में वह आगे आने वाले चार पांच सालों में दूर हो जायेंगी।

उद्योग के लिए जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं हम लोगों ने काफी तरह-तरह की रियायतें दी हैं इस तरह के इलाकों के लिए, जिस में ट्रांसपोर्ट सबसिडी भी शामिल है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस भी और उस के साथ-साथ इस तरह के उद्योग धन्धे कोई वहां लगाना चाहे तो उस को हम कई तरह की आर्थिक सुविधाएं देते हैं। इसलिए हमें यह उम्मीद है कि जिन प्रश्नों के बारे में माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है उन का समुचित उत्तर हम इस पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ढूंढ सकेंगे।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी मौका दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : हिल एरिया से तो आप हैं नहीं ।

श्री लालजी भाई: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, राजस्थान प्रदेश पहाड़ी तो है ही, उस का कम भाग रेगिस्तान कहलाता है, उस राज्य में पहाड़ी इलाका ज्यादा है और उस के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई हैं जैसे सड़क बनाना, तालाब बनाना, नहर आदि सिंचाई के साधन बनाना, पानी की व्यवस्था करना इन सब के लिए कई पंचवर्षीय योजनाओं में पूंजी रखी गई लेकिन उस विकास की पूंजी को सही ढंग में नहीं लाया गया है । आजकल तो सरकार की पालिसी ऐसी बन गई है कि आया चुनाव और विकास शुरू कर दिया इन इलाकों में, वोट ले लिया, लेकिन अनापशनाप का भ्रष्टाचार इन विकास के कामों में हो रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह पूंजी सही ढंग से सही स्थान पर लगे इस के लिए कोई ऐसा दल सरकार नियुक्त करने वाली है जो कि इसकी समय-समय पर जांच करती रहे और पूंजी का सही ढंग से उपयोग हो सके ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह माननीय सदस्य का कहना बिलकुल गलत है कि चुनाव से विकास से हम को कोई संबंध रखते हैं । इस से कोई मतलब नहीं है । जहां पर जैसी आवश्यकता होती है और जहां पर हम समझते हैं कि प्राथमिकता देनी चाहिए वहां हम प्राथमिकता देते हैं और राजनैतिक प्रश्नों को हम विकास के कामों से लिंक नहीं करते हैं ।

माननीय पाणिग्रही जी के प्रश्न के उत्तर में मैंने इस बात को साफ किया था जो कि विशेष दल की बात कही या जो पैसा दिया गया है उस का दुरुपयोग होने की बात कही गई है, उस संबंध में मैंने साफ किया कि जो हम सबप्लान्स बना रहे हैं उस के अन्तर्गत इस तरह का प्रावधान किया जाएगा कि जो जिस इलाके के लिए खास कर के जो आदिवासी इलाके हैं और इस तरह के जो पहाड़ी इलाके हैं उन के लिए जो धन दिया जायगा, जिस राशि का प्रावधान किया जायगा वह उसी के लिए उपयोग हो सकती है ।

श्री लालजी भाई : अध्यक्ष महोदय, सही ढंग से पूंजी नहीं लग रही है, इसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूं ।

श्री प्रताप सिंह नेगी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी के लिए जो पर्वतीय विकास परिषद् बनाई गई है क्या वह पंगु ही रहेगी या उस को कोई स्टेटस दिया जायगा जिससे विकास कार्य वहां हो सके ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जो विकास परिषद उत्तर प्रदेश में बनाई गई है उस का काम ही यह है कि केन्द्रीय सरकार को और प्रादेशिक सरकार को वह अपनी राय और अपने जो उस के सुझाव हैं वह देती रहे जिस से कि कोई भी क्षेत्र ऐसा बाकी न बच जाए विकास का जिस की अपेक्षा हो और मैं समझता हूं कि वह विकास समिति ठीक से काम कर रही है ।

श्री वीरभद्र सिंह : पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सड़कों का निर्माण आवश्यक है । किन्तु अभी तक पंचवर्षीय योजना में इस के लिये जो रुपया दिया गया है वह पर्याप्त सिद्ध नहीं हुआ है। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ अतिरिक्त धन देने की व्यवस्था की जा रही है और यदि यह संभव नहीं है तो क्या जो स्टेट के प्लानस है उन में से इस कार्य के लिये

प्रोजेक्ट को प्रायरटी करने के लिए राज्यों को इत्तला दी जायेगी या नहीं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह माननीय सदस्य ने ठीक बात कही है कि अभी तक पहाड़ी इलाकों में सड़कों के निर्माण की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए । इसलिए इस वक्त पांचवीं पंचवर्षीय योजना मे हम लोगों का यह प्रस्ताव है कि पहाड़ी इलाकों मे सड़कों के विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय और जो अभी वार्षिक योजनाओं के बारे मे बातचीत हुई थी उसमें जो पहाड़ी इलाकों के मुख्य मंत्री और योजना मंत्री इत्यादि आए थे उन से इस के बारे मे विशेष रूप से कहा गया है कि वे राज्य सरकार की मदद से और हम जो उन को सहायता देंगे उस से मिल कर सड़कों के विकास की तरफ विशेष रूप से ध्यान दें और मैं आशा करता हू कि इस से माननीय सदस्य को काफी सतोष होगा ।

श्रीमती सहोदरा बाई राय एक कमेटी जो अभी अरुणांचल प्रदे गई थी, उन के साथ वहा मैं भी गई थी । वहा का विकास सड़को का न शिक्षा का किसी चीज का कुछ भी नही हुआ है । जो विकास हुआ है वह न के बराबर है । वहा की जनता ने हम से शिकायत की है कि सोलह साल से वहां कलेक्टर और एस डी ओ जमे हुए हैं उत्तर प्रदेश के इसलिए वहां सही तरीके से काम नही होता है । तो मैं यह कहना चाहती हू कि ये जो सोलह सोलह साल से कलेक्टर और एस डी ओ वहां हैं उन को बदलिए तो काम जल्दी हो । वहा का पैसा तो बहुत सा उन की जेब में जाता है । वहां के आदिवासी कहते हैं कि आप आ कर कहिए हमारा विकास हो हमारे यहां बिजली लगे, हमारे यहां सड़कें बनें, खाने जाने के साधन बनें । इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी उस के लिए कदम यह उठाएं जिस से इस इलाके का विकास हो और उन की तरक्की हो ।

श्री विद्याचरण शुक्ल · अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने जैसा कहा है कि वहां कुछ नही हुआ है, यह बात ठीक नहीं है । वहा काफ़ी काम हुआ है । लेकिन मैं इस बात को मजूर कर सकता हू कि वहा बहुत कुछ होना अभी बाकी है । इसके लिये जो व्यक्ति वहा पर लगे हुये हैं, वे विशेष रूप से काम कर रहे हैं । हालाकि उन की भी स्वय की काफी समस्यायें हैं । इसके अलावा वे लोग ऐसे इलाको मे रह कर काम करते है जहा साधारणतया कोई आदमी काम नही करना चाहता है, लेकिन वे लोग वहा लगकर जीवनदान करके काम कर रहे हैं ।

आपने जो प्रशासकीय समस्याये उठाई है—उनकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं । यदि हम समझते है कि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा समय कही रहते हो गया है और उनकी उपयोगिता नही है तो उसको वहा से हटा देते हैं । माननीय सस्दया ने यह ठीक ही कहा है कि हमे अरुणाचल प्रदेश की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये—हमारी भी यही योजना है और पाचवी पचवर्षीय योजना मे हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं ।

Programmes for Chandigarh Radio Station

*23 SHRI RAJDEO SINGH Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state

(a) whether programmes for Chandigarh Radio Station are prepared in Akashvani Bhavan in Delhi;

(b) if so, the reasons why Chandigarh officers and staff work in Delhi when studio and other facilities are now available in Chandigrah; and